# ACHIEVERS IAS ACADEMY

## SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

# HINDI

DATE

**04/08/2023**

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

New Patliputra Colony, Road No. 4A, Near Tennis Court, Patna-13

# THE HINDU 04.08-2023 National

## सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट और सभी छोटे फैक्टर पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के सभी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इन उत्पादों को देश में लाने और ग्राहकों को बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

इस कदम से अल्पकालिक लैपटॉप असेंबली पर असर पड़ सकता है जो विदेश में असेंबली पर निर्भर हैं, जैसे डेल, एचपी, लेनोवो और एप्पल। इस कदम से इस बाजार में घरेलू क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
FY22 और FY24 के दौरान, भारत ने चीन से 9446 मिलियन डॉलर मूल्य के लैपटॉप का आयात किया, हांगकांग 1442 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर था। सिंगापुर 1318 मिलियन डॉलर और ताइवान 229 मिलियन डॉलर क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।

## ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए नौ लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाने की संभावना है

केंद्र की महत्वाकांक्षी ₹72000 करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना में बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 9.64 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। राज्य मंत्री (पर्यावरण) अश्विनी चौबे ने राज्यसभा में बताया।

ग्रेट निकोबार परियोजना:-- गृह मंत्रालय द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण के रूप में चिह्नित इस परियोजना में ग्रेट निकोबार की 130 वर्ग किलोमीटर प्राचीन भूमि का उपयोग किया जाएगा। एक उन्नत बंदरगाह, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और 450 एमवीए और सौर ऊर्जा आधारित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर बिजली संयंत्र। इसे पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। लेकिन इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चुनौती दी गई, जिसने इस पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

महान निकोबार सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है जिसमें वनस्पतियों की 650 प्रजातियाँ और जीव-जंतुओं की 330 प्रजातियाँ हैं। काटे जा रहे पेड़ों की भरपाई हरियाणा में वनीकरण से की जाएगी।

*Great nicobar Southern among Andman and Nicobar islands*

### 'सेव द चिल्ड्रेन' ने अपना एफसीआरए परमिट खो दिया है।

गृह मंत्रालय के पास विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत अनुमति है।

सेव द चिल्ड्रन यूके स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। यह 116 देशों और भारत के 16 राज्यों में काम करता है। इसकी भारतीय शाखा का नाम "बाल रक्षा भारत" है। इसका काम स्वास्थ्य, शिक्षा और भूख और संघर्ष में कमजोर बच्चों पर केंद्रित है।

यह कुपोषण पर एक धन उगाहने वाले अभियान के दौरान सरकार के रडार पर आया था, जिस पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा "जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया गया"।

हमारे एफसीआरए आवेदन का नवीनीकरण न होना हमारे लिए आश्चर्य की बात है। बाल रक्षा भारत के एक प्रवक्ता ने कहा, हम सरकार के साथ काम करेंगे और स्थिति को जल्द से जल्द सुलझाने में मददगार होंगे।

### एचसी द्वारा एएसआई सर्वेक्षण के आदेश के बाद ज्ञानवापी पैनल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली मस्जिद समिति ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ ही घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गुरुवार को एएसआई को परिसर की "जांच" करने की अनुमति दे दी गई। मामला 4 अगस्त को सुनवाई के लिए दर्ज किया गया है.

### SC: क्या आप अनुच्छेद 370 की तुलना बुनियादी ढांचे से कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा कि क्या जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को संविधान के मूल ढांचे के बराबर माना जा रहा है?

वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी, और प्रावधान ने 1957 के बाद "स्थायी चरित्र" प्राप्त कर लिया था जब जम्मू-कश्मीर संविधान सभा भंग हो गई थी, जिससे अनुच्छेद अपरिवर्तित रह गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि "अनुच्छेद 370 को हटाना पूरी तरह से एक राजनीतिक कार्रवाई थी"।

सीजेआई ने सवाल किया, "आप यह कैसे कह सकते हैं कि संसद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए अपनी प्रारंभिक संशोधन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी?"जस्टिस एस के कौ लने सवाल किया, "क्यायहअनुच्छेद 370 को संविधान के मूलढांचे के सिद्धांत के बराबर करने जैसा नहीं होगा जब आप कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता?"

### संसद में:

### शीर्षक: राज्यसभा में बिना विपक्ष की गैरमौजूदगी में तीन बिल पास हो गए

द. राज्यसभा ने गुरुवार को तीन विधेयक पारित किए, विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर पर कार्यवाही का बहिष्कार किया।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक और अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक गुरुवार को।

अपतटीय खनिज क्षेत्र विधेयक पेश करते हुए कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले के खनन की नीलामी पहले भ्रष्टाचार से प्रभावित थी, सरकार ने खनिजों और धातुओं की नीलामी के लिए एक अचूक तंत्र बनाया है।

अन्य दो विधेयक अप्रचलित और स्वतंत्रता-पूर्व कानूनों को निरस्त करने पर जोर देते हैं।

## वॉकआउट के बीच लोकसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया

## केंद्र में छह बैठे लोगों के साथ, विपक्ष मणिपुर बहस पर गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रहा है

अब तक बीजेपी मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्षी दल पीएम से संसद में मणिपुर पर बोलने की मांग कर रहे थे.

विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक में विपक्ष के नेता पीयूष गोयल को बताया गया कि विपक्ष नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है।

## विवाद के बीच डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश

इससे पहले केएस पुट्टास्वामी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था।

## सरकार ने लोकसभा में डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया -

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं:

कानून के तहत कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कौन सा डेटा एकत्र किया जा रहा है और उनका उपयोग किस लिए किया जा रहा है

व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहने वाली संस्थाओं को ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है।

भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा

उपयोगकर्ता को संस्थाओं को प्रदान किए गए अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने या संशोधित करने का अधिकार मिलेगा।

यह आईटी नियम 2000 की धारा 43ए को रद्द कर देता है जिसके तहत कंपनियों को डेटा के दुरुपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देना पड़ता है।

## अरिहा के मामले पर जोर देने के लिए भारत ने जर्मन दूत को बुलाया:

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने पालक देखभाल में बच्चे की स्थिति पर जर्मन राजदूत को तलब किया था।

इससे पहले अरिहा की मां धारा शाह ने गुरुवार को दोनों सदनों के सांसदों से मुलाकात की.

मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां पत्रकारों से कहा, "कम से कम, हमारा मानना है कि एक भारतीय के रूप में इस बच्चे के सांस्कृतिक अधिकारों और अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि 2021 के मामले को "उच्च प्राथमिकता" दी जा रही है।

## अरिहा शाह मामला:

अरिहा शाह के माता-पिता जर्मनी में काम करते थे जब वह 7 महीने की थी, अरिहा को जर्मन अधिकारियों द्वारा पालन-पोषण की देखभाल के लिए दे दिया गया था। डॉक्टरोंने अरिहा को तब प्रताड़ित घोषित कर दिया जब उसके जननांगों के पास चोट के निशान और शरीर के अन्य हिस्सों में क्रूर चोटों के निशान पाए गए।

उसे पालक देखभाल के लिए दिया गया था। उसकेमाता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिनबाद में माता-पिता को बरी कर दिया गया। सितंबर 2021 में जब अरिहा 8 महीने की थी। पालन-पोषणदेखभाल द्वारा लिया गया था।

जर्मनी की अदालतों ने अभी भी अरिहा की देखभाल जर्मन यूथ सर्विसेज (जुगेंडमेंट) द्वारा करने को कहा है। भारतीय पक्ष की मांग है कि अरिहा को भारत में किसी पालक देखभाल के लिए दिया जाए।

## पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी

पाकिस्तानी सेना ने नए सुरक्षा समझौते CIS-MOA पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है
सीआईएस-एमओए-संचार। अंतरसंचालनीयताऔर सुरक्षा समझौता ज्ञापन
अमेरिका उन गुटों के साथ सीआईएस-एमओए पर हस्ताक्षर करता है जिनके साथ वह घनिष्ठ सैन्य और रक्षा संबंध बनाए रखना चाहता है। यह अन्य देशों को हथियार और हार्डवेयर बेचने के लिए अमेरिकी रक्षा को कवर प्रदान करता है।
समझौता 2020 में समाप्त हो गया, और उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। समझौते से संकेत मिलता है कि अमेरिका आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को कुछ सैन्य हार्डवेयर बेच सकता है।

## सुरक्षा चिंताएँ बढ़ने पर नाइजर में तख्तापलट समर्थकों की रैली।

लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने वाले तख्तापलट के समर्थन में गुरुवार को नाइजर की राजधानी नियामी में हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली।
1960 में नाइजर की आजादी को चिह्नित करने वाले प्रदर्शन में फ्रांस विरोधी नारे और रूस समर्थक और पुतिन समर्थक नारे लगाए गए। भीड़ने "फ्रांस मुर्दाबाद", "रूस जिंदाबाद", "पुतिन जिंदाबाद" के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियोंमें से एक ने कहा, "हम उन फ्रांसीसी को नहीं चाहते जो 1960 से हमें लूट रहे हैं - वे तब से वहीं हैं और कुछ भी नहीं बदला है"। बज़ौम सरकार फ्रांस के प्रति अत्यधिक निर्भर थी, जिससे कई लोग नफरत करते हैं।
राष्ट्रपति बज़ौम के नेतृत्व में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का 26 जुलाई को तख्तापलट कर दिया गया। श्री बज़ौम गिरफ़्तार हैं। अमेरिकीराष्ट्रपति ने बज़ौम की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है। रविवार को पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक ईसीओडब्ल्यूएस ने बज़ौम की तत्काल रिहाई का आह्वान किया और उन्हें सत्ता में वापस लाने या सैन्य हस्तक्षेप के "अंतिम विकल्प" का सामना करने के लिए कहा।
कई देशों ने नाइजर से अपने इमैन्सी स्टाफ को वापस बुला लिया है।

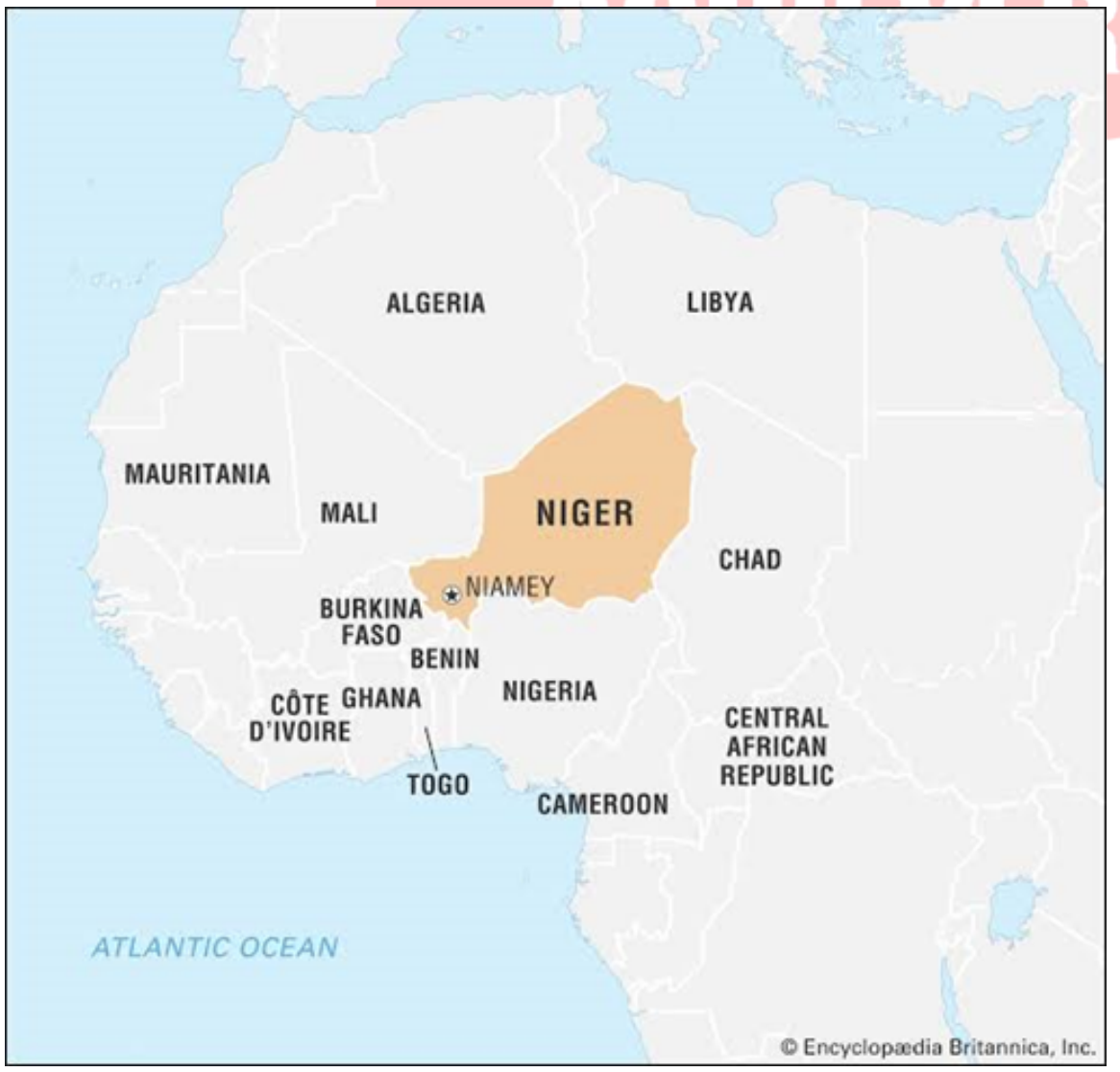


***Niger***

## सऊदी, कुवैत ने क्षेत्र पर ईरान के दावे को खारिज कर दिया

अपतटीय तेल क्षेत्र जिसे ईरान में अराश और कुवैत और सऊदी अरब में डोर्रा के नाम से जाना जाता है, तीनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद में है। इसेसुलझाने के कई प्रयास असफल रहे हैं। रविवारको ईरान बिना किसी समझौते के भी अन्वेषण को आगे बढ़ा सकता है। कुवैतीऔर सऊदी अधिकारियों ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि इसमें अन्वेषण करने का अधिकार केवल उन्हें ही है।

फारस की खाड़ी क्षेत्र दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन जैसे कई तेल उत्पादक देशों के पास इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में तेल और गैस क्षेत्र हैं।

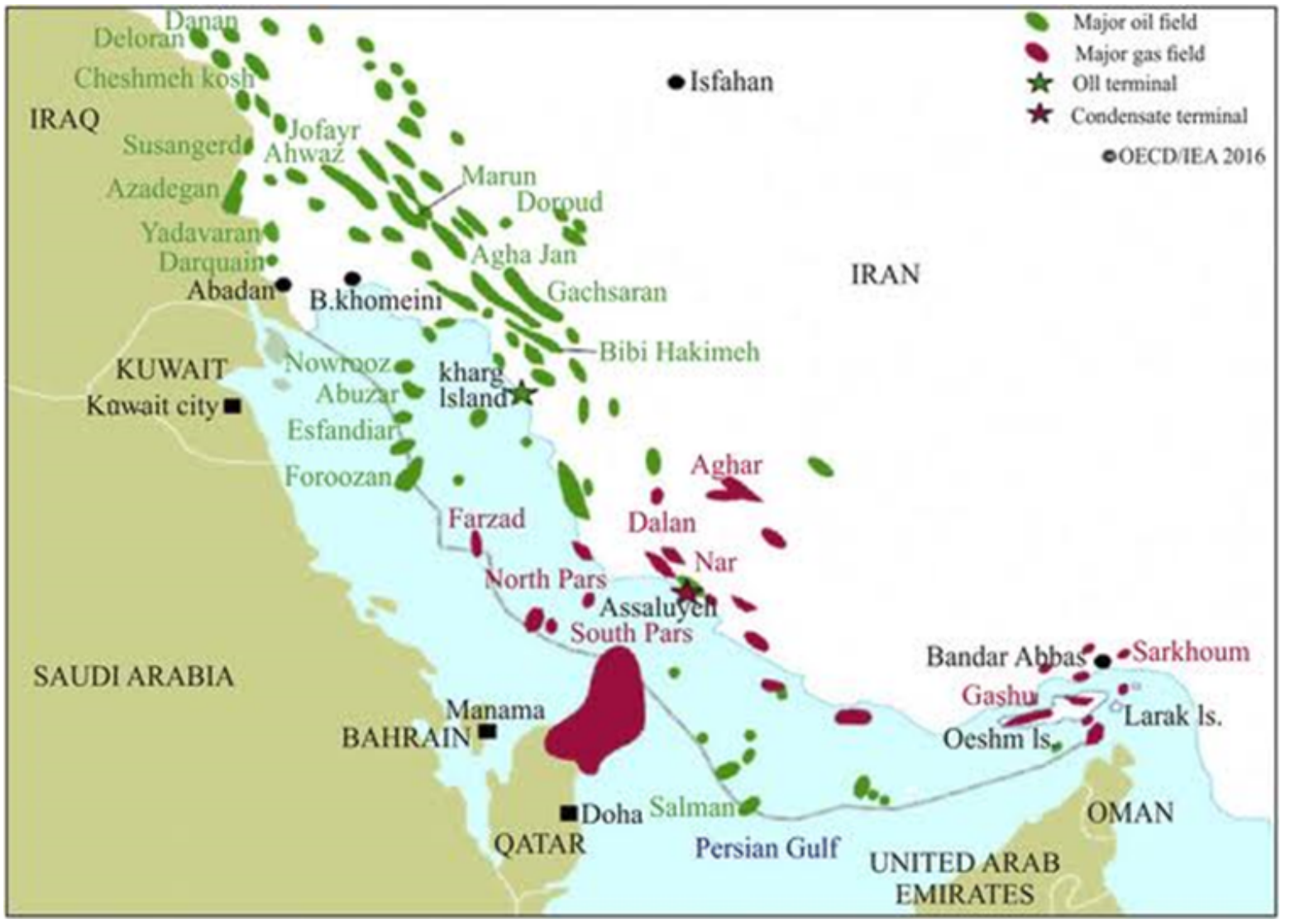


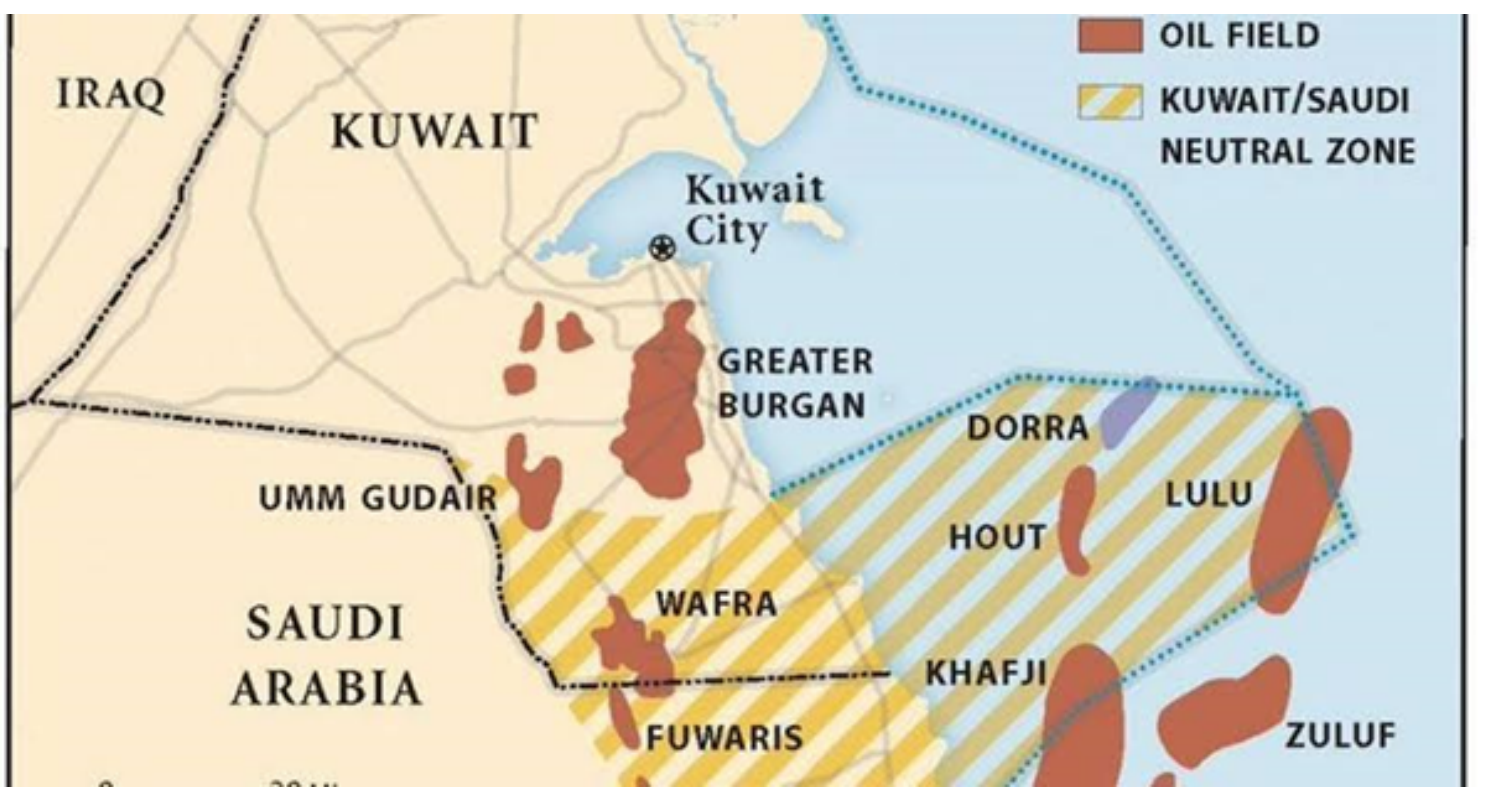


**पर्शियन खड़ी में तेल का कुआं**

### चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर ट्रंप को जज का सामना करना पड़ेगा।

मंगलवार को ट्रम्प पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने का आरोप लगाने वाले एक मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायविभाग के विशेष वकील ने ट्रम्प पर 2020 के चुनावों से पहले राष्ट्रपति चुनाव में हार की भरपाई करने के उनके प्रयासों, कैपिटल हिल में दंगा, अमेरिका को धोखा देने की साजिश और आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश समेत चार अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

गुरुवार को वह कोर्ट में पेश होंगे.

## Editorial- 1

# अधिकार बनाना :

## साम्प्रदायिक संघर्ष की स्थिति में राज्य को निष्पक्ष रहना चाहिए:

### संपादकीय के बारे में:

संपादकीय नूंह में हाल की हिंसा के बारे में है। यह संभावित कारणों के बारे में बात करता है और कहता है कि राज्य को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए।

### हिंसा की शुरुआत और प्रसार :

नूंह क्षेत्र एक है.हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों का गढ़ गाय को लेकर रडार पर है.लंबे समय से तस्करी.

हाल के दिनों में पुलिस ने इलाके में अपराधियों पर जमकर नकेल कसी है.क्षेत्र बनता है ए.अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की बड़ी आबादी.

जब हिंदू समुदाय का एक धार्मिक जुलूस जा रहा था तो अल्पसंख्यक समुदाय की भीड़ ने पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी, इसमें भाग लेने वाले अधिकांश हिंदुओं को पास के मंदिर में शरण लेनी पड़ी। होमगार्ड की जान चली गई.

बाद में जवाबी कार्रवाई में, हिंदू पक्ष ने मस्जिद में तोड़फोड़ की और एक इमाम की हत्या कर दी। , क्षेत्र में कई लोगों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

## Editorial- 2

# तीन प्रहार

## अमेरिका में मतदाताओं का चरम स्तर का राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा जा रहा है

### संपादकीय के बारे में:

संपादकीय डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया अभियोग के बारे में है। इसमें उस स्थिति के बारे में बताया गया है जो आगे चलकर अमेरिका में पैदा हो सकती है।

### ट्रम्प के अभियोग के बारे में

मंगलवार को ट्रम्प पर चार आरोपों में धोखाधड़ी, गवाहों से छेड़छाड़, नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ साजिश और आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया।

बाधा डालने के आरोप 6 जनवरी, 2021 की घटना से संबंधित हैं, जिसमें ट्रम्प के समर्थकों ने उनके द्वारा उकसाए जाने पर कैपिटल हिल (यूएस कांग्रेस) तक मार्च किया था, जहां चुनाव परिणामों को मंजूरी दी जा रही थी। भीड़ ने कम से कम 140 कानून प्रवर्तन अधिकारियों को घायल कर दिया और पत्नी पैमाने पर हंगामा मचाया। ट्रम्प को दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है, एक मॉडल के लिए अपना पैसा जुटाने का और दूसरा गोपनीय दस्तावेज़ अपने पास रखने का।

### भविष्य की संभावनाओं :

2024 में चुनाव होने हैं, अगर इनमें से किसी में भी ट्रंप दोषी साबित हुए तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अमेरिका में कोई भी जेल से चुनाव लड़ सकता है. और अगर ट्रम्प जीत गए तो वह जेल से देश चलाएंगे। सरकार को अर्थव्यवस्था, नागरिक अधिकार, विदेश नीति आदि कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का ख़तरा है कि अमेरिकी असाधारणता अतीत की बात बन सकती है।